जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर
Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 270 प्रभात उदयपुर, शुक्रवार 1 अगस्त, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

राहुल 15 दिन की यात्रा करेंगे बिहार में

राहुल के साथ तेजस्वी यादव भी कई स्थानों पर शामिल होंगे, तथा छोटी -छोटी सभाएं आयोजित करेंगे उन लोगों के साथ जिनका नाम मतदाता सूची से कटा है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जुलाई। बिहार में लगभग 70 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच टकराव तेज़ होता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है।

आगामी दिनों में संसद में इस मुद्दे को लेकर हंगामा जारी रहने की पूरी संभावना है, और ऐसे में सरकार के लिए किसी भी प्रकार का विधायी कार्य करना लगभग असंभव हो जाएगा।

चुनाव आयोग द्वारा आज देर रात मतदाता सूची जारी किए जाने के बाद, जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें इसकी जानकारी मिलेगी और वे संगठित होकर अपना विरोध दर्ज कराना शुरू करेंगे और आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता सामने आने लगेगी।

विपक्ष अगले सप्ताह के मध्य में संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च करेगा, तब तक बिहार के प्रभावित लोग ज़ोर-शोर से अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर चुके होंगे।

इससे पहले, राहुल गांधी 4 अगस्त को कर्नाटक जा रहे हैं, जहाँ वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा की गई कथित गड़बड़ी की जानकारी साझा करेंगे, जहाँ करीब 1 लाख 7 हजार वोट चुराए गए थे।

भाजपा उस लोकसभा क्षेत्र के चार अन्य विधानसभा क्षेत्रों में हार गई थी, लेकिन एक विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े अंतर की वजह से, वह लोकसभा सीट जीतने में सफल रही थी।

कांग्रेस ने पिछले छह महीनों में इस पूरे मामले का विस्तृत अध्ययन किया है, और इस अध्ययन के निष्कर्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा करेंगे, ताकि यह साबित किया जा सके कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर जनता के जनादेश को चुराने का काम कर रहा है।

राहुल के दिल्ली लौटने के बाद, विपक्ष चुनाव आयोग के खिलाफ एक नया हमला शुरू करेगा।

राहुल गांधी बिहार में 15 दिन की यात्रा पर भी निकल रहे हैं, जहाँ कुछ जगहों पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी उनके साथ जुड़ेंगे। यह यात्रा गाडी से, पदयात्रा के रूप में, छोटी-छोटी जनसभाओं और संवाद सत्रों के ज़रिए होगी, जो पटना के गांधी मैदान में एक बडी जनसभा का रुप ले लेगी।

इस यात्रा के दौरान, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उन मतदाताओं से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- राहुल का सोच है, इस यात्रा के बाद, बिहार में मतदाताओं का नाम काटने की प्रक्रिया (एस.आई.आर.) संसद से सड़क तक गूँजेगी।
- बिहार से पहले राहुल कर्नाटक भी जायेंगे, और इस बात का ढिंढोरा पीटेंगे कि कैसे चुनाव आयोग ने एक विधानसभा सीट पर एस.आई.आर. प्रक्रिया से एक लाख सात हजार मतदाता ''चुराये'', तथा भाजपा इस लोकसभा सीट की बाकी चारों विधानसभा सीटों पर हारी, लेकिन, क्योंकि एक विधानसभा सीट पर मार्जिन इतना अधिक था कि भाजपा वो लोकसभा सीट जीत गई।
- गत छः महीने से कांग्रेस ऐसे डेटा (आकड़े) इकट्ठे करने का काम कर रही है, तथा इन आकड़ों का अंतिम निष्कर्ष राहुल, आम सभा में बतायेंगे।
- तथा यह साबित करेंगे कि चुनाव आयोग भाजपा को जीत हासिल कराने में पूर्ण सहयोग कर रहा है।

महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी

जयपुर, 31 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को सुनने के लिए तय की गई एकलपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने को कहा है, जहां जोशी की जमानत पर आगामी सप्ताह में सुनवाई होगी। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाएं सुनने के लिए नया रोस्टर आ गया है। ऐसे में प्रकरण को नियमित बेंच के समक्ष भेजा जा रहा है।

- ईडी कोर्ट में महेश जोशी, पुत्र रोहित सहित डेढ़ दर्जन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया जा चुका है।

जमानत याचिका में कहा गया कि प्रकरण में उन्हें फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद, बिना कोई परिस्थिति बदले, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा, ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जिस जूनून से अमेरिका भारत को सबक सिखाने में जुटा है वह उसकी खीज व कुंठा का सबूत है

कुंठा इसलिए कि ट्रंप की ''डील मेकिंग'' की चेष्टा लगभग विफल ही रही

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

वॉशिंगटन, 31 जुलाई। भारत को निश्चित रूप से ट्रम्प द्वारा लगाए गए टैरिफ का सीमित आर्थिक प्रभाव झेलना पड़ेगा। हालांकि, यदि भारत अपने निर्यात आधार में विविधता लाने का ठोस प्रयास करे, तो इस प्रभाव को अंततः नियंत्रित किया जा सकता है।

जहाँ यह अधिक चोट पहुँचा सकता है, वह है अमेरिका की समग्र नीति में बदलाव। अमेरिका में भारत-विरोधी तत्वों की कोई कमी नहीं है, जो पाकिस्तान को भारत को परेशान करने के लिए एक साधन के रूप में देखना चाहते हैं। ये लॉबी पहले से ही सक्रिय हो चुकी है।

अमेरिका ने पाकिस्तान में एक ''विशाल तेल भंडार'' विकसित करने की घोषणा की है और अंततः उस तेल को भारत को बेचने की योजना बनाई है। यह तो स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान ने अचानक इतना बड़ा तेल भंडार कैसे खोज लिया, लेकिन पाकिस्तान के प्रति अमेरिकी रुख में बदलाव महत्वपूर्ण है।

यह भू-राजनीतिक समीकरण में बदलाव का संकेत देता है। चीन पहले से ही पाकिस्तान को भारत विरोधी गतिविधियों में खुले और गुप्त रूप से समर्थन देता रहा है। अब यदि अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया तो व्यापक मोर्चे पर भारत के लिए यह गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है।

ईरान, जो कूटनीति में अनुभवी है, पहले ही यह भांप चुका है कि कैसे भारत को लेकर अमेरिकी रुख में बदलाव पूरी तरह एक नए परिप्रेक्ष्य को जन्म दे सकता है। भारत में ईरानी दूतावास ने खुद एक बयान जारी कर अमेरिका के इस कदम को ''आर्थिक साम्राज्यवाद'' करार दिया है।

इस बयान से एक नए तरह के गठजोड़ की बात सामने आती है, जिसमें ईरान कहता है कि अमेरिका के नए साम्राज्यवाद के खिलाफ एक व्यापक वैश्विक गठबंधन बनना चाहिए। ईरान ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत से इस नए ''ग्लोबल साउथ'' के नेतृत्व की अपील की है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ट्रम्प की ''डील मेकिंग'' (दादागिरी पूर्ण सौदेबाजी) असफल रही रुस के सामने, तथा जैसे तैसे यूरोपियन यूनियन, जापान व ब्रिटेन को भी सौदेबाजी स्वीकार करने के लिये मना सका, पर, गाज़ा में दादागिरी के बावजूद उसके शांति स्थापित करने के प्रयास विफल ही रहे।
- अतः ट्रंप अपना ''फ्रस्ट्रेशन'' भारत पर उतार रहा है।
- यह उल्लेखनीय है कि, ट्रम्प ने, रुस से आयल खरीदने के कारण भारत पर पेनल्टी लगाने की बात कही। पर, यह पेनल्टी क्या होगी, इसे परिभाषित नहीं कर पाया है। चीन को भी पेनल्टी की धमकी दिये काफी समय हो गया है, पर, अब तक यह निश्चित नहीं कर सका है, अमेरिका कि ''पेनल्टी'' कितनी होगी, और कैसे लगेगी।

'25 प्रतिशत टैरिफ से भारत की जी.डी.पी. 0.2 प्रतिशत घटेगी'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जुलाई। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले से देश की आर्थिक विकास संभावनाओं को झटका लग सकता है।

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि इसका असर कितना बड़ा होगा, क्योंकि ट्रंप ने 25 प्रतिशत टैरिफ के अलावा एक अनिर्दिष्ट ''दंडात्मक शुल्क'' (पैनल्टी) लगाने की भी घोषणा की है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस दंड की बारीकियों की जानकारी मिलने के बाद ही इस फैसले के वास्तविक आर्थिक प्रभाव का सही आंकलन किया जा सकेगा।

रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने एक बयान में कहा, अमेरिका की ओर से प्रस्तावित टैरिफ (और पैनल्टी) हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक है और इसलिए यह भारत की जीडीपी वृद्धि दर के लिए बाधा बन सकता है। इस नुकसान व गिरावट की गंभीरता इस बात पर निर्भर करेगी कि जुर्माना कितना बड़ा लगाया गया है।

आईसीआरए पहले ही इस वित्त वर्ष के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत से घटाकर 6.2 प्रतिशत कर चुकी है, टैरिफ वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए।

एक अन्य ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने कहा कि ये टैरिफ ''विकास के लिए नकारात्मक'' है और इससे भारत की को 0.2 प्रतिशत तक का नुकसान हो सकता है।

भारतीय शेयर बाजार ने इस खबर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और व्यापार के पहले दिन बाजार लाल निशान में खुला।

फंड मैनेजर नीलेश शाह ने कहा, बाजार को उम्मीद थी कि अमेरिका-भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों को देखते हुए कोई टैरिफ समझौता हो जाएगा।

भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों में कई दौर की व्यापार वार्ताएँ हो चुकी हैं, जिनमें भारत ने अमेरिका को खुश करने के लिए बर्बन व्हिस्की और मोटरसाइकिल जैसे उत्पादों पर टैरिफ में कटौती भी की थी। लेकिन अमेरिका का भारत के साथ 45 अरब डॉलर (लगभग 33 अरब पाउंड) का व्यापार घाटा है, जिसे ट्रंप कम करना चाहते हैं।

- इकोनॉमिक एक्स्पर्ट्स का मानना है कि टैरिफ आशंका से ज्यादा लगाई गई है, अतः जी.डी.पी. 0.2 प्रतिशत तो घटेगी ही। पर, पेनल्टी का सही आंकड़ा आने पर, यह पूर्णतया साफ होगा, कि भारत की ग्रोथ पर, कितना टोटल होगा।

फिलिपीन्स राष्ट्रपति 4 अगस्त को भारत आयेंगे

नयी दिल्ली, 31 जुलाई। फिलिपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर अगले महीने की चार तारीख को भारत की पांच दिन की राजकीय यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा में उनके साथ प्रथम महिला मैडम लुईस अरनेटा मार्कोस और एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, अन्य गणमान्य व्यक्ति , वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रपति मार्कोस आठ अगस्त को फिलिपींस लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएँगे।

- पांच दिन की यात्रा में वे बेंगलुरु भी जायेंगे।

राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद यह मार्कोस की पहली भारत यात्रा होगी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मार्कोस पांच अगस्त को द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। मार्कोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भी राष्ट्रपति मार्कोस से मुलाकात करेंगे।

'मेरी रिहाई अब कोई मायने नहीं रखती, इस मुकदमे ने मेरी जिन्दगी तबाह कर दी है'

प्रज्ञा ठाकुर, ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित व पांच अन्य आरोपी 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद बरी हुए न्यायालय से

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जुलाई। गुरुवार को भगवावस्त्र -धारी पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 2008 के मालेगाँव ब्लास्ट केस में सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इससे पहले मुम्बई की अदालत ने कहा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि छः लोगों की जान लेने वाले विस्फोट में कथित रुप से काम में ली गई बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की थी।

जज ने कहा, जहाँ अभियोग पक्ष ने यह सिद्ध किया है कि ब्लास्ट हुआ था, वहीं यह पक्ष सिद्ध नहीं कर सका कि विस्फोटक पदार्थ कथित रुप से प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल, ''एलएमएल'' फ्रीडम पर फिट किया हुआ था। साध्वी ने जज से कहा कि उनका दोष मुक्त होना अब कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ''इस केस ने मेरी जिन्दगी बरबाद कर दी।''

जज ने कहा, मोटरसाइकिल का चेचिस नंबर मिटा दिया गया था और इंजन नंबर पर भी संदेह है। ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि साध्वी (प्रज्ञा ठाकुर) उसकी मालिक थीं या उनके पास वह गाड़ी थी।'' यह फैसला, भारत में आतंकवाद के सबसे लंबे समय तक चले केसों में से एक में दिया गया है। इस केस में बम बनाने के आरोपी, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को भी बरी कर दिया गया।

यह फैसला 17 साल की लंबी कानूनी लड़ाई का अंत है जिसमें मध्यप्रदेश के एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की बेटी साध्वी प्रज्ञा पर इस आतंकी हमले की साजिश करने का आरोप लगाया गया था, तथा कहा गया था कि इस हमले का उद्देश्य 2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जैसे पूर्व के आतंकी हमलों का बदला लेना था। उस समय प्रज्ञा ठाकुर की उनकी उम्र करीब 38 वर्ष थी। उन्हें ''हिंदू आतंकवाद'' का चेहरा कहा गया, जो 2008 के मालेगाँव धमाकों के बाद एक चर्चित शब्द बन गया था। उन पर धमाके के लिए लोगों को जुटाने का आरोप था, जबकि उनके सह-आरोपी, पूर्व सैन्य अधिकारी कर्नल पुरोहित पर विस्फोटक देने का आरोप था। गुरुवार को, दोनों को पांच अन्य आरोपियों के साथ, बरी कर दिया गया।

जब अदालत ने यह फैसला सुनाया, तब प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपी अदालत में मौजूद थे। उन्होंने जज से कहा, ''मैंने शुरू से ही कहा था कि किसी को पूछताछ के लिए बुलाने का कोई आधार होना चाहिए। मुझे बुलाया गया, गिरफ्तार किया गया, और प्रताड़ित किया गया। इसने मेरी पूरी ज़िंदगी नष्ट कर दी। मैं एक साध्वी का जीवन जी रही थी, लेकिन मुझे आरोपी बना दिया गया और कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। मैं जीवित इसलिये हूं क्योंकि मैं सन्यासी हूं। भगवा को बदनाम किया गया, यह एक साज़िश थी। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, और जो दोषी हैं उन्हें भगवान सज़ा देंगे।''

- प्रज्ञा ठाकुर को ''हिन्दू आतंकवाद'' का नाम दिया था उनके विरोधियों ने तथा प्रज्ञा ठाकुर ने रिहाई के बाद कोर्ट में यह भी कहा, कि मुझे गिरफ्तार किया गया तथा, यातनाएं दी गईं, अगर में जीवित हूं तो केवल इसलिये कि मैं, सन्यासी हूं। उन्होंने साजिश के तहत ''भगवा'' को बदनाम करने की कोशिश की, पर भगवा जीता।''

बिहार में मतदाता की मसौदा सूची आज जारी होगी

नयी दिल्ली, 31 जुलाई। बिहार में विधान सभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के अगले चरण में सूची के मसौदे का प्रकाशन शुक्रवार को किया जाएगा। इसके बाद, कल से ही मसौदा सूची में छूट गये किसी भी पात्र नाम को जुड़वाने या जुड़े हुए अपात्र नाम को कटवाने या किसी त्रुटि के संशोधन के लिए एक माह तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राज्य के मतदाताओं के नाम एक संदेश में कहा, बिहार के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा राज्य के सभी जिलों में सभी मान्यता प्राप्त रानीतिक दलों को इसकी भौतिक और डिजिटल प्रतियां भी दी जाएंगी। आयोग के अनुसार स्थानीय बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और एजेंटों ने घर-घर जाकर जानकारी लेने के अभियान में पाया की सूची में 22 लाख मतदाताओं (2.83 प्रतिशत) की मृत्यु हो चुकी है, 36 लाख (4.59 प्रतिश) स्थायी रूप से राज्य छोड़ कर जा चुके हैं, सात लाख मतदाताओं (0.89 प्रतिशत) के नाम एक से अधिक जगह दर्ज हैं।

- सभी जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भौतिक डिजिटल प्रतियां दी जायेंगी।

क्या दिल्ली व वॉशिंगटन एक दूसरे के प्रति विश्वास दोबारा स्थापित कर पाऐंगे?

ट्रम्प की बेलगाम भाषा व असंतुलित व्यापारिक निर्णयों ने, पिछले पच्चीस साल से धीरे -धीरे मजबूत और गहरे हुए रिश्तों को लगभग उखाड़ फैंका है

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 31 जुलाई। भारत-अमेरिका संबंधों में अचानक आई गिरावट, जो राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की आक्रामक बयानबाज़ी और भारतीय निर्यातों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के निर्णय से और अधिक प्रभावित हुई है, ने पिछले 25 वर्षों में लगातार गहरे होते संबंधों को एक ऐतिहासिक झटका दिया है। दोनों ओर के विश्लेषकों ने इसे 1998 के बाद का सबसे बड़ा कूटनीतिक संकट बताया है, जब भारत के परमाणु परीक्षणों के कारण वाशिंगटन के साथ रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। यह अचानक यू टर्न ऐसे समय पर आया है, जब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के केवल कुछ ही महीने बीते हैं और जिससे, नई व्यापार वार्ताओं के एक और दौर से ठीक पहले, रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर गंभीर असर पड सकता है।

इस संकट के मूल में ट्रंप के तीखे आरोप हैं, कि भारत अनुचित व्यापारिक नीतियों का पालन कर रहा है। उन्होंने न केवल दंडात्मक टैरिफ की धमकी दी, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ''मृत'' कहकर उसका अपमान भी किया। अपनी ऑनलाइन टिप्पणियों में उन्होंने भारत के रूस के साथ रिश्तों और ब्रिक्स में भारत की सक्रिय भूमिका का भी मज़ाक उड़ाते हुए, उसे अमेरिका के हितों के लिए खतरा बताया। इस बयानबाज़ी के परिणामस्वरूप, नीति विश्लेषकों और रणनीतिकारों ने चेतावनी दी है कि दशकों की मेहनत से बने संबंध अब टूटने की कगार पर हैं।

एक अगस्त से भारतीय निर्यातों पर लागू होने वाला 25 प्रतिशत टैरिफ दरअसल व्यापार नीति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर भारत को सज़ा देने की कोशिश है, क्योंकि ट्रंप के अनुसार, भारत अपमानजनक गैर-आर्थिक व्यापार बाधाओं और गलत भू-राजनीतिक झुकाव का दोषी है। इस कदम ने भारत को चीन सहित अन्य व्यापारिक साझेदारों की तुलना में कहीं ज़्यादा कठोर तरीके से निशाना बनाया है, जबकि अमेरिका के साथ भारत का ट्रेड सरप्लस ग्लोबल स्टैण्डर्ड्स तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

ट्रंप के नज़रिए से, भारत के रूस के साथ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- बुश, ओबामा, और बाइडन के शासनकाल में अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य सोच था, भारत को चीन के ''काउन्टर वेट'' के रुप में विकसित करना।
- पर, अब ट्रम्प का भारत की इकॉनमी को ''डैड'' (मृत) घोषित करना, व भारी टैरिफ लगाना भारत को चीन व रुस के नजदीक फैंक रहा है, विशेषकर, ब्रिक्स, एस.सी.ओ. व ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में पूर्णतया सक्रिय होने पर मजबूर कर रहा है।
- अब तक भारत, मॉस्को के साथ पुराने रिश्तों व अमेरिका से डिफैन्स, आतंकवाद से मुकाबला आदि क्षेत्रों में सहयोग के बीच संतुलन बिठाने का प्रयास करता रहा है, पर, ट्रम्प के नये ''करतबों'' ने, इस संतुलन को एकदम बिगाड़ दिया है।

विपक्ष ने दिन भर लोकसभा में नारेबाजी की

नयी दिल्ली, 31 जुलाई। लोकसभा में विपक्षी दलों ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को लेकर गुरुवार को भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दो बार के स्थगन के बाद, चार बजे तीसरी बार जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरु की, विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा और नारेबाजी करते हुए सदन के बीचोंबीच आ गये। हंगामे के बीच ही वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी टैरिफ पर संसद में बयान दिया और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच वार्ता जारी है, लेकिन भारत अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करेगा।

बिरला ने मंत्री का वक्तव्य पूरा होने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- शोरगुल के बीच वाणिज्य मंत्री ने अमेरिकी टैरिफ पर बयान दिया।